

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 560वीं बैठक दिनांक 12/03/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9060/2022 Shri Tapan Vaishnav Onwer, Village - Umariya Jagir, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP), MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.990 ha. (Stone - 38000 cum per annum, Waste - 2000 cum per annum) (Khasra No. 07), Village - Umariya Jagir, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 07), Village - Umariya Jagir, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP) 3.990 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/03/22 को परियोजना प्रस्तावक आनलाइन और उनकी ओर श्री उमेश मिश्रा, पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 234 दिनांक 16/06/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 11.990 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में दक्षिण-पश्चिम दिशा में 160 मीटर तथा दक्षिण दिशा में 230 मीटर पर कच्चा रोड़ है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज क्षेत्र में कुछ

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

लगे हैं। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. दक्षिण-पश्चिम दिशा में 160 मीटर तथा दक्षिण दिशा में 230 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे।
5. लीज क्षेत्र में कुछ लगे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम उनकी संख्या, ऊँचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

2. Case No 9055/2022 Shri Sohan Singh, Onwer, Asravad Bujurg, Dist. Indore, MP - 452010 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.10 ha. (8000 cum per annum) (Khasra No. 199/1/2), Village - Malikhedi, Tehsil - Bicholi Hapsi, Dist. Indore (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 199/1/2), Village - Malikhedi Kala, Tehsil - Bicholi Hapsi, Dist. Indore (MP) 1.10 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/03/22 को परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि आत्माराम पारिया और उनकी ओर श्री शिशुपाल वर्मा, पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ. आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 544 दिनांक 24/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, जिसका कुल रकबा 2.90 हे. है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 544 दिनांक 24/02/2022 के अनुसार प्रस्तावित खदान से 5.16 किलोमीटर दूर रालामण्डल अभ्यारण्य है। अतः उनके द्वारा एन.बी.डब्ल्यू.एल. (National Board for Wildlife) से अनुमति हेतु आवेदन क्रमांक **FP/MP/QR/6237/20222**, दिनांक 23/2/22 को किया गया है तथा अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही उत्खनन कार्य किया जावेगा।

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 125 मीटर पर आबादी है, 45 मीटर पर पूर्व दिशा में उद्योग तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 285 मीटर पर रेणुका माता का मंदिर भी स्थित हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया कि लीज क्षेत्र पूर्व से खोदा हुआ है तथा अधिकांश लीज क्षेत्र में पानी भरा है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्ष 2014 तक खनन कार्य किया गया है एवं उसके उपरांत खदान बंद है। समिति ने पाया कि परियोजना के प्रस्तावित स्थल का गूगल इमेज (11/2017 तथा 04/2021) के अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है तथा यह ई.आई.आई नोटिफिकेशन, 2006 के अनुसार वॉयलेशन (Violation) का प्रकरण है। अतः इस स्थिति में इस प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता अतः नस्ती सिया को आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जावे।

3. Case No 9056/2022 Shri Ramvaran Singh S/o Late Shri Barfi Singh, Village - Dongarpur, Tehsil & Dist. Morena, MP Prior Environment Clearance for Soil Quarry in an area of 1.0 ha. (2000 cum per annum) (Khasra No. 3371, 3375, 3382), Village - Jinganee, Tehsil - Morena, Dist. Morena (MP)

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3371, 3375, 3382), Village - Jinganee, Tehsil - Morena, Dist. Morena (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) दिनांक 17/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार विचाराधीन खदान स्थल के उत्तर-पूर्वी दिशा में 105 मीटर पर नहर है तथा लीज 02 भागों में आवंटित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पी.पी. ने बताया कि एक हेक्टेयर एरिया पूर्ण करने हेतु लीज 02 भागों में आवंटित की गई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, 02 मीटर से अधिक उत्खनन नहीं किया जायेगा, कोई भी वृक्ष नहीं काटा जायेगा तथा चिमनी भी प्रस्तावित स्थल पर स्थापित नहीं की जावेगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान पी.पी. ने बताया कि लीज क्षेत्र में खदान मालिक का घर है, जो सामान रखने के काम आता है। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि
 - लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ हैं, जिसे नहीं काटा जायेगा।
 - लीज क्षेत्र से चिमनी की स्थापना नहीं की जावेगी।
 - 02 मीटर गहराई तक ही उत्खनन किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/3/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्वाईल – 2,000 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 07.41 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.75 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख :-

सी. ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम जिगनी के ऑगनवाड़ी केन्द्र में पोषण आहार का वितरण।	20,000
किसानों को गुग्गल पेड़ का वितरण और वृक्षारोपण व रख-रखाव का प्रशिक्षण।	5,000
जिगनी में महामारी में आवश्यक सावधानियों के लिए ग्रामीणों का स्वच्छतकिट (हैंड सेनेटाइजर, हेण्ड ग्लब्स और नाक का मुखौटा) के रूप में वितरण और प्रशिक्षण	5,000
योग	30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, खमेर, शीशम, खैर, सुबबूल, चिरोल आदि। (बीज बोने के साथ)	390
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, खमेर, शीशम, चिरोल, पुत्ररनजीवा, मोलश्री आदि।	330
विद्यालय में और ग्रामीणों को पौधे बांटे जाएंगे	नीम, महुआ, निम्बू, कटहल, गुग्गल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	480

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

4. Case No 9057/2022 Smt. Suman Rajoriya W/o Shri Girraj Prasad, LIG - 768, Near Tulika Convent School, Old Housing Board Colony, Dist. Morena, MP - 476001 Prior Environment Clearance for Soil Quarry in an area of 2.0 ha. (4400 cum per annum) (Khasra No. 435/1, 436, 438, 442), Village - Nepari, Tehsil - Kailaras, Dist. Morena (MP)

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 435/1, 436, 438, 442), Village - Nepari, Tehsil - Kailaras, Dist. Morena (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1570 दिनांक 16/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, जिसका कुल रकबा 4.0 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार विचाराधीन खदान के अंदर 04 पेड़ लगे हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, 02 मीटर से अधिक उत्खनन नहीं किया जायेगा, कोई भी वृक्ष नहीं काटा जायेगा तथा चिमनी भी प्रस्तावित स्थल पर स्थापित नहीं की जावेगी तथा लीज 02 भागों में स्वीकृत किया गया है। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि
 - लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ हैं, जिसे नहीं काटा जायेगा।
 - लीज क्षेत्र से चिमनी की स्थापना नहीं की जावेगी।
 - 02 मीटर गहराई तक ही उत्खनन किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/3/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्वाईल - 4,400 मी.3 प्रति वर्ष।

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.90 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.25 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.45 लाख :-

सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम नेपारी के ऑगनवाड़ी केन्द्र में पोषण आहार का वितरण ।	30,000
किसानों को गुग्गल पेड़ का वितरण और वृक्षारोपण व रख-रखाव का प्रशिक्षण ।	10,000
ग्राम नेपारी में महामारी में आवश्यक सावधानियों के लिए ग्रामीणों का स्वच्छता किट (हैंड सेनेटाइजर, हेण्ड ग्लब्स और नाक का मुखौटा) के रूप में वितरण और प्रशिक्षण	5,000
योग	45,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातिया	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, खमेर, कचनार, शीशम, खैर, सुबबूल, चिरोल आदि। (बीज बोने के साथ)	700
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, खमेर, शीशम, चिरोल, पुत्ररनजीवा, मोलश्री आदि।	900
विद्यालय में और ग्रामीणों को पौधे बांटे जाएंगे	नीम, मुहुआ, निम्बू, कटहल, गुग्गल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	800
	योग	2400

5. **Case No 9058/2022 Shri Saboor Ahmad, Onwer House No. 12, Near Jama Masjid Badi Paartalai, Tehsil - Badi, Dist. Raisen, MP - 464665, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (6000 cum per annum) (Khasra No. 196/56), Village - Panari, Tehsil - Budni, Dist. Sehore (MP)**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 196/56), Village - Panari, Tehsil - Budni, Dist. Sehore (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 3744 दिनांक 21/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

एकल प्रमाण-पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 3744 दिनांक 21/12/2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान से 3.714 किलोमीटर दूर रातापानी अभ्यारण्य है तथा वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, सिहोर ने भी पत्र क्रमांक 964 दिनांक 20/5/20 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रस्तावित खदान से 3.714 किलोमीटर दूर रातापानी अभ्यारण्य है तथा प्रस्तावित क्षेत्र का रातापानी अभ्यारण के पारिस्थितिक संवेदी जोन के ग्रामों की सूची में उल्लेखित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 410 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में जल भराव क्षेत्र हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मुरुम खनिज उत्खनन के दौरान ब्लैस्टिंग का प्रस्ताव नहीं है तथा पूर्व क्षेत्र में जो जल भराव है वह वर्ष 2013 के आस-पास ग्रामीणों द्वारा मिट्टी निकालने के कारण निर्मित हो गया है कोई तालाब या जल रोकने वाली संरचना नहीं है इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एकल प्रमाण-पत्र (खजिन शाखा) दिनांक 21/12/2021 में भी इसका उल्लेख नहीं है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित लीज क्षेत्र में काफी हरित क्षेत्र परिलक्षित हो रहा है जिसके संदर्भ में पी.पी. ने बताया कि यह झडियां हैं जो गूगल इमेज वर्षाकाल की होने के कारण दिख रही है तथा उत्खनन के दौरान कोई भी वृक्ष नहीं काटा जायेगा तथा पूरे खदान क्षेत्र में खनन नहीं किया जावेगा, खनन पूर्वी दिशा में 1.0 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जावेगा तथा पश्चिम दिशा के क्षेत्र को नॉन माइनिंग जोन छोड़ा जावेगा । इसी प्रकार पूर्व क्षेत्र में जो गड़ढे दिख रहे हैं, वह काफी पुराने हैं तथा ग्रामीणों द्वारा ऊपर की मिट्टी खोदने के कारण निर्मित हो गया है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ पश्चिम दिशा के क्षेत्र को नॉन माइनिंग जोन दिखाते हुए सरफेस मैप ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरुम – 6000 मी.3 प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 12.42 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.55 लाख प्रति वर्ष ।

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख :-

सी. ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
शासकीय हाई स्कूल, डुंगरिया में फर्निचर (10 बेंच, 5 लकड़ी की कुर्सियाँ) और 2 आलमारी, लाइब्रेरी के लिए।	60,000
शासकीय प्राथमिक स्कूल, गोर में 20 छायादार वृक्षों (कदम्ब, कचनार, करंज, बहुनिया एवं अन्य प्रजातियों) को ट्री गार्ड के साथ लगाना	10000
योग	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधों का प्रस्तावित स्थान	लगाए जाने वाले पौधों के प्रकार	मात्रा
बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, पीपल, करंज, खमेर, चिरोल, सीताफल, कुम्भी, बीजा, अमलतास, दहिमन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, नीम, पीपल, कचनार, कुम्भी, शीशम, दहिमन, आम, बरगद, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, सीताफल, आँवला, नीबू, बेल, आम, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	500
ग्राम पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केंद्र	सीताफल, कदम, नीम, कुम्भी, बीजा, शीशम, दहिमन, पीपल, पाकड़, बरगद, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
कुल योग		2400

6. **Case No 9059/2022 Shri Babulal Panwar Onwer, House No. 217, Ward No. 16, Haatkeshwar Ashram, Semli Chacha, Tehsil - Polaykalan, Dist. Shajapur, MP - 465220, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.69 ha. (8085 cum per annum) (Khasra No. 61), Village - Khamkheda Dewas, Tehsil - Polaykalan, Dist. Shajapur (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 61), Village - Khamkheda Dewas, Tehsil -

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

Polaykalan, Dist. Shajapur (MP) 2.69 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 49 दिनांक 01/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पश्चिम दिशा में 375 मीटर रोड हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज उत्खनन के दौरान आवंटित क्षेत्र में कोई पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव नहीं है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 8085 मी.3 प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.72 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.36
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख :-

सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम खामखेडा देवास के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के स्कूल में 1 कम्प्यूटर, प्रिन्टर, टेबल के साथ और 1 वाटर प्यूरीफायर ।	80,000
ग्राम खामखेडा देवास के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 20 छायादार वृक्षों (कदम्ब, कचनार, करंज, बहुनिया एवं अन्य प्रजातियाँ) को ट्री गार्ड के साथ लगाना	10000
योग	90,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022**

प्रस्तावित स्थान	लगाए जाने वाले पौधों के प्रकार	मात्रा
बैरियर जोन	करंज, खमेर, चिरोल, सीताफल, कुम्भी, बीजा, अमलतास, दहिमन, सीस्सू, नीम, पीपल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, नीम, पीपल, कचनार, कुम्भी, शीशम, दहिमन, आम, बरगद, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ ।	300
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, सीताफल, आवंला, नीबू, बेल, आम, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	800
ग्राम पंचायत भवन एवं आंगनवाड़ी केंद्र	सीताफल, कुम्भी, नीम, बीजा, शीशम, दहिमन, पीपल, पाकड, बरगद, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1000
कुल योग		3600

**7. प्रकरण क्रमांक 9032/2022 - श्री अब्दुल सलाम, सिविल लाईन जिला झांसी (म.प्र.)
स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 850/4, रकबा 4.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन क्वेरी -
85000 मी.³, ग्राम शकुली, तहसील एवं जिला निवाडी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति
बावत्**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आनलाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 850/4, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम शकुली, तहसील एवं जिला निवाडी (म.प्र.) पर स्थित है।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 560वीं दिनांक 12/03/22 एवं 557वीं दिनांक 03/02/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है। अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

- 8. Case No 9046/2022 Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, Dr. Mahak Bhandari, Authorised Signatory, SAIMS Hospital, Indore - Ujjain State Highway, Gram - Bhanwrasia, Tehsil - Sanwer, Distt. Indore, (M.P.) – 453555. Prior Environment Clearance for Construction of Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences , Total Plot Area: 14.78 ha, Total Built-up Area: 1,42,770.16 sqm (Hospital Area = 33525.34 sqm, Institutional Area = 66497.46 sqm & Residential Area = 42747.36 sqm), Khasra No. – 8, 14/1, 14/1/1, 14/1/2, 15, 15/2, 8, 26/2, at Village - Bhanwrasla, Tehsil - Sanwer, Distt. – Indore (M.P.). Total Plot Area: 14.78 ha, Total Built-up Area: 142770.16 sqm (Hospital Area = 33525.34 sqm, Institutional Area = 66497.46 sqm & Residential Area = 42747.36 sqm), Env. Consultant Shri Shubham Dubey, M/s. Envisolve LLP, Indore.**

This is a case of Prior Environment Clearance for Expansion of Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, Total Plot Area: 14.78 ha, Total Built-up Area: 142770.16 sqm (Hospital Area = 33525.34 sqm, Institutional Area = 66497.46 sqm & Residential Area = 42747.36 sqm), Khasra No. – 8, 14/1, 14/1/1, 14/1/2, 15, 15/2, 8, 26/2, at Village - Bhanwrasla, Tehsil - Sanwer, Distt. – Indore (M.P.). Cat. 8(a) Building and Construction Projects.

प्रकरण आज दिनांक 04/03/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति द्वारा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण एक और अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का समिति निर्णय लेती है फिर भी यदि परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो यह प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा।

आज परियोजना प्रस्तावक की तरफ से श्री अनुपम सिंह तथा पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट से संबंधित निम्न विवरण प्रस्तुत किए :-

PARTICULARS	EXISTING	PROPOSED	TOTAL PROPOSED
Total Solid Waste	1428 kg/ day	746 Kg/day	2174 Kg/day
Power Requirement	1310 KW	0.00 KW	1310 KW
DG set details	DG set of 250 KVA in 2 no., 62.5 KVA in 1 no., 35 KVA in 1 no. & 500 KVA in 1 no.	0.00	DG set of 250 KVA in 2 no., 62.5 KVA in 1 no., 35 KVA in 1 no. & 500 KVA in 1 no.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

Water Requirement in KLD	Total Water Requirement=702.9 KLD Fresh water requirement=451.20 KLD Fresh Water: 451.20 KLD Flushing: 251.7 KLD Sewage Gen: 650 KLD	Total Water Requirement=287.1 KLD Fresh water requirement=75.80 KLD Fresh Water: 75.80 KLD Flushing: 101.30 KLD Sewage Gen: 125 KLD	Total Water Requirement=970 KLD Fresh water requirement=527 KLD Fresh Water: 527 KLD Flushing: 353 KLD Sewage Gen: 775KLD
Number of Beds	800 Beds	600 Beds	1400 Beds
Sump well & OH Tank STP & ETP Rainwater Harvesting Garbage Disposal Service Block (Substation, DG Set, etc.)	U G Sump – 58.17 KL, 34.14 KL, 16.21 KL KLD , Fire Fighting: 55.5 KL, 95.32 KL STP-650 KLD & ETP- 50 KLD 21 No of RWH Pits Yes, as per norms Yes, as per norms	STP- 125 KLD & ETP- 150 KLD	U G Sump – 58.17 KL, 34.14 KL, 16.21 KL KLD , Fire Fighting: 55.5 KL, 95.32 KL STP-775 KLD & ETP- 200 KLD 21 No of RWH Pits Yes, as per norms Yes, as per norms
Front MoS/Rear MoS	12 MTS/9 MTS	12 MTS/9 MTS	12 MTS/9 MTS
Height of Building	18.0 MTS	18.0 MTS	18.0 MTS

LAND BREAK-UP DETAILS

Detailed Land Break-up

Total land area	= 1,47,880.00 m ²
Permissible ground coverage @ 25%	= 36,970.00 m ²
Proposed ground coverage @ 17.79%	= 26,302.32 m ²
Permissible built-up area @ 1.5	= 2,21,820.00 m ²
Proposed built-up area	= 1,42,770.16 m ²

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

Chronology of the Project

Date	Activities
23.05.2011	Site visit to SAIMS by MPPCB, Regional Office, Indore.
18.07.2011	In the site visit report by MPPCB, violations found.
16.08.2011	Reply to site visit report submitted by SAIMS.
21.12.2011	Letter from MPPCB to stop construction work.
02.07.2012	Board of resolution: Construction started in 2008 which continued upto 2012. BUA < 1.5 lac m2 completed and hence falls under 8(a) category.
14.08.2012	Application submitted to MPSEIAA for expansion under case no. 839/2012 for plot area 191920 m2 and 141229.148 m2; Built-up Area (16481.92 m2 for expansion).
10.10.2012	In 106th meeting of SEAC, it is considered case of violation as PP constructed more than 124747 m2 of Built-up Area between 2004 and 2011 without EC and ordered for ground visit by site committee.
12.10.2012	Site visit by Committee, it was suggested that PP may withdraw the present application for expansion and submit a fresh application for entire Built-up Area of 141228 m2.
10.01.2013	Revised application submitted for total Built-up Area of 142770.16 m2.
02.02.2013	Presentation held in 119th meeting of SEAC and PP was asked to submit the reply to certain queries.
22.04.2013	Query reply submitted.
23.07.2013	Presentation held in 136th meeting of SEAC and case recommended for EC.
01.11.2013	SEIAA in its 149th meeting on 26.09.2013, out rightly rejected the project.
15.04.2014	PP submitted letter to Principal Secretary, GoMP.
27.06.2014	PP submitted a letter to SEIAA to reconsider the case.
11.07.2014	PP submitted a letter to RO, MPPCB apologizing for the violations made.
17.07.2014	Case filed against SAIMS by MPPCB.
26.08.2014	SEIAA in its 157th meeting stated that it is not clear whether SEIAA has the power to review the case and a letter should be sent to MoEF&CC to clarify the procedure.
22.12.2014	Activities involving industrial shed, school, college, hostel for educational institution are exempted from taking EC.
09.06.2015	In clarification to the above notification, it was published that in case of medical universities, the component of hospitals will continue to require EC.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

01.06.2018	Application made to MP SEIAA for Environment Clearance under Violation portal.
21.08.2018	ToR recommended in 326th meeting of SEAC.
19.09.2018	ToR Granted by SEAC.
08.08.2019	EC Considered in 561th meeting of SEIAA.
05.09.2019	EC granted by SEIAA.
24.02.2022	Applied for expansion of project.
12.03.2022	Presentation before SEAC committee.

आज परियोजना प्रस्तावक की तरफ से श्री अनुपम सिंह तथा पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्तमान प्रकरण में प्रोजेक्ट के एरिया/क्षेत्रफल तथा निर्मित क्षेत्र में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है सिर्फ विस्तारों की क्षमता 800 बेड से 1400 बेड बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव नेशनल मेडिकल कौंसिल की मार्गदर्शिका में परिवर्तन के कारण किया जा रहा है जिसमें एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी पूर्व कम से कम 05 फीट निर्धारित थी जो अब 03 फीट हो गई है । उपरोक्त मार्गदर्शिका को ध्यान में रखते हुए बेड क्षमता बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है । बेड क्षमता का विस्तार होने के कारण 02 अतिरिक्त कमशः घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र 125 केएलडी तथा औद्योगिक दूषित जल उपचार संयंत्र 150 केएलडी का लगाया जायेगा । इस क्षमता विस्तार के कारण बढ़ी हुई मात्रा के जीव चिकित्सकीय अपशिष्ट इंदौर में स्थापित सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. में निष्पादित कराये जायेंगे जिसके सदस्यता उपलब्ध है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारीयों प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

1. Copy of MoEF&CC compliance report of earlier EC Conditions.
2. PP's undertaking regarding CER activities & plantations as suggested by the committee.

PP vide letter dated 12.03.2022 has submitted the revised plantation species details which was placed before the committee. After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Expansion of Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, from 800 beds to 1400 beds in the existing premises itself. Total Plot Area: 14.78 ha, Total Built-up Area: 142770.16 sqm (Hospital Area = 33525.34 sqm, Institutional Area = 66497.46 sqm & Residential Area = 42747.36 sqm), Khasra No. – 8, 14/1, 14/1/1, 14/1/2, 15, 15/2, 8, 26/2, at Village - Bhanwrasla, Tehsil - Sanwer, Distt. – Indore (M.P.) Cat. 8(a) subject to the following special conditions:

Statutory Compliance

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
- ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

- iv. 05 Diesel power generating sets 250 kVA *02 nos. & 500 kVA* 01 nos, 62.5 kVA* 01 nos, 35 kVA* 01 nos. proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- xi. The gaseous emission from DG sets 250 kVA *02 nos. & 500 kVA* 01 nos, 62.5 kVA* 01 nos, 35 kVA* 01 nos. shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during operation phase is 970 KLD out of which 527 KLD is fresh water requirement and 775 KLD will be the total recycled water generated, out of which 353 KLD recycled water will be used for flushing and 244 KLD water will be used for horticulture.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiii. For rainwater harvesting, 21 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 1035 m³/hr .Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.
- xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.
- xix. Sewage shall be treated in the MBBR based STP Capacity - 775 KLD (01 New STP of 125 KLD) & ETP Capacity- 200 KLD (01 New ETP of 150 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
- xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 775 KLD capacity (based on MBBR based technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
- xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
- vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

- i. Total waste 2174 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 1304.4 Kg/day and non- organic waste 652.2 Kg/day), Inert waste 217.4 Kg/day, E- waste 1566 Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
- ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

- i. Total 1786 trees has been already planted in the area of 48,800 m² (32.99 % of total plot area) which is developed as greenbelt development.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

- ii. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).
- iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iv. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- v. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points
 - d. Parking norms as per local regulation
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iii. Total proposed Parking's arrangement for 1706 ECS (1706 ECS for open parking).
- iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP & CER

- i. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 31.2 Cr as capital and Rs. 1.33 Cr as recurring cost for this project.
- ii. For this project PP has proposed Rs 12.50 lakh as Corporate Environment Responsibility (CER) under following activities:
 - We will plant 2500 No. of trees @ INR 300/ tree in our campus and on the banks of Kshipra & Khan river confluence point including plantation of khair slips & Nagarmotha on river bank through Forest Department, Ujjain.
 - Following activities will be taken in Nahar Jhabua village @ INR 5,00,000/ year under following schemes:
 1. Health checkups camps twice a year at Nahar Jhabua Village.
 2. Awareness towards oral hygiene in Nahar Jhabua village.
 3. Free medicine distribution at Nahar Jhabua village.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

4. Pediatric camps and diet supplements for newly born children at the village Nahar Jhabua.
 5. Dietary advice to avoid malnutrition and diet supplements at the village Nahar Jhabua.
-
- iii. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
 - iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
 - v. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
 - vi. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

XI. Miscellaneous

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

9. Case No. - 9061/2022 The Executive Engineer, Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, Dist. Khandwa, MP,) Prior Environment Clearance for Aulliya Medium Irrigation Project at Village Roshani/Aulliya, Distt. - Khandwa, (M.P.) CCA – 5000 ha.Cat. 1(c) River Valley Projects. Env. Consl.: M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon.

This is case of Prior Environment Clearance for Aulliya Medium Irrigation Project at Village - Roshani / Aulliya, Tehsil & Dist. Khandwa, (MP)

Background of the project:

The above case file was placed before the committee for discussion in the SEAC 514th Dated 21.09.2021. During scrutiny of case file it was observed by the committee that TOR was recommended in 297th SEAC meeting dated 08-11-17 which was subsequently approved by SEIAA in their 456th meeting dated 16-11-17. However, so far PP has not submitted the EIA report and as per issued TOR letter no 544 dated 13/12/17, TOR will expire on 07/11/21 but its validity can be extended for one year. Committee further observed that a WP (No. 6240/2021) has been filled by the petitioners wherein SEIAA, WRD and Land Acquisition Officer have been made respondents. On perusal of petition in the "Relief Prayed For", it is observed that mainly two issues are raised by the petitioners i.e. illegal construction of dam and issues related to R&R from respondents no. 02 & 03.

Committee deliberated on the issue and recommends that being rainy season the dam site may not be approachable and thus on the basis of issues mentioned in WP, SEIAA initially shall obtain factual status about the dam construction without environmental clearance (as reported by the petitioners in WP No. 6240/2021) from E.E., Water Resource Division, Khandwa (PP) & Chief Engineer, Narmada Tapti Basin, WRD,

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

Indore as they also have filed reply in this case as respondent no.02. Secondly, for site verification (if required after obtaining status report as above), visit shall be carried out by a joint team comprising of following expert members:

1. Representative from Ministry of Environment, Forest and climate Change, Regional Office, Bhopal.
2. Representative from Central Pollution Control Board, Zonal Office, Bhopal.
3. Expert Member from SEIAA.
4. Expert Member from SEAC.
5. Representative from District Administration Department.
6. Representative from office of the Executive Engineer Water Resources Department, Water Resources Division, Khandwa, M.P., as Co-ordinator.

Committee decided that as submitted above case file may be sent to SEIAA for kind consideration of submission made above and to take necessary action.

The case was discussed in SEIAA in their 689th Meeting dated 21/10/21 wherein it is recorded that Representative of PP was present during the meeting and informed that a team of Senior Officials of the WRD Department will visit to get a factual report of the Project Site & submit the same in SEIAA. Hence, it is decided after monsoon period a team of expert members of the SEAC may also visit the site by coordinating with WRD officials and assess factual status of the site, so that authority can take decision accordingly.

The case was scheduled in the in the agenda in the SEAC 529th meeting held on Dated 24.11.2021 wherein PP remains absent. Committee observed that as per the minutes of SEIAA, senior Officials of the WRD Department have been instructed to visit the site and submit a factual report of the Project site however, till date no such report is received. Committee after deliberation recommends that Senior Officials of the WRD Department shall visit the site as early as possible and submit the factual report about the project site and present the same before SEIAA and SEAC.

The case was scheduled for the discussion in the 541st SEAC meeting dated 20.01.2022 on Aulliya Medium Irrigation Project at Village Roshani/Aulliya, Distt. - Khandwa, (M.P.) CCA – 5000 ha., Cat. 1(c) River Valley Projects , wherein Shri P. Joshi , S.E., Indore Region & Project Incharge Smt. Megha Chourey, E.E., Division Khandwa and Smt. Divayani Billore E.E. , SCADA Office , Bhopal, from Water Resources Department, Govt. of M.P., were attended the meeting in person or through video

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

conferencing in this meeting. Smt Diwayani Billore E.E. , SCADA Office , Bhopal quoted the letter written by Office of the Chief Engineer Narmada Tapti Basin, WRD, Indore, letter of Shri N.N. Gandhi N-T Basin WRD, Indore the letter was also received SEAC through Speed post vide no. 479/work/-26/NT/21, dated 23.11.2021.

wherein letter stated that –

“Aulliya Medium Irrigation Project is located in Village Roshani of Khalwa Tehsil, , Distt. – Khandwa. It is proposed on River Ghorapachhar, which is tributary of Chhota Tawa River. The project involve construction of 1782 meters long and 20.80 m high, earthen dam which is 72.50 m central spill way . It is proposed to irrigate a command area of 5000 ha. For which Administrative approval of Rs. 165.08 Crores to was accorded to the project in June 2017.

Under Resettlement & Rehabilitation (R&R) - the project involves a total of 384.442 ha. of private land under submergence. Land acquisition for the same has been carried out as per provisions of RFCTLAR Act 2013. The R&R has been completed for 90% of the area under submergence. Process is underway to complete acquisition of the remaining 10% area mainly due to ownership disputes.

Forest Clearance: The project involves 54.60 ha. of forest land submergence. Both Stage1 & Stage 2 clearances for the same have been obtained from MoEF&CC. The project pertains to Cat. 1(c) , Category B of the EIA notification 2006 as the CCA is less than 10,000 ha. Also , the EMP report was submitted to SEIAA.

Present status of the project: Aulliya Medium Irrigation Project involves construction of 25.50 m high & 1805 m long earthen dam with a 72.50 m long central spillway portion. The project also involves construction of pressurised pipe irrigation network to irrigate 6703 ha. of command area in Khalwa Tehsil of Khandwa Distt.

At present, earth work has been carried out in 1693.50 lengths of left and right flanks of proposed dam. This work has been done non- overflow section. A sluice well has been constructed on RD 1605 m for discharge of River water. Construction work of spillway in nalla portion was restricted at original river bank level to maintain natural flow of water. Nalla closure has not been done. At present no work is being done in head works. The laying of pipelines for pressurized irrigation system in the command area is under process.

Conditions under which work was started:

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

- *Water demand by farmers & villagers due to water scarcity in the command area .*
- *In compliance of guideline issued by GoI during COVID- 19 pandemic to provide employment to migrant labours under MNREGA.*
- *It is project of public utility with absolutely no personal or private interest involve.*
- *The project provides immense socio-economic benefits to the ST population of entire command.*
- *It is pertain to mention that nalla closre has not been done and flow of the river has not been obstructed.*
- *The project authorities have assured that nalla closure and impounding of the dam has not been in anticipation of impeding Environmental Clearance.*

The committee after detailed discussion it was observed that the as per factual status submitted by Office of the Chief Engineer Narmada Tapti Basin, WRD, Indore, vide letter No. vide no. 479/work/-26/NT/21, dated 23.11.2021 of Shri N.N. Gandhi, Chief Engineer, N-T Basin WRD, Indore. As per the submitted report By C.E. WRD, it is very much clear that they have carried out the partial construction work.

“Earth work has been carried out in 1693.50 lengths of left and right flanks of proposed dam. This work has been done non- overflow section. A sluice well has been constructed on RD 1605 m for discharge of River water. Construction work of spillway in nalla portion was restricted at original river bank level to maintain natural flow of water. Nalla closure has not been done. At present no work is being done in head works. The laying of pipelines for pressurized irrigation system in the command area is under process.

So, as per the submitted report by Office of the Chief Engineer Narmada Tapti Basin, WRD, Indore, vide letter No. vide no. 479/work/-26/NT/21, dated 23.11.2021 of Shri N.N. Gandhi, Chief Engineer, N-T Basin WRD, Indore, factual status is very much clear so committee feels there is no need of further site visit is required.

In this context PP should furnished implementation of Environmental Management Plan, comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan as mentioned in the MOEF&CC Notification New Delhi, the 8th March, 2018 S.O. 1030 (E) and submit present status of court direction through SEIAA.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

SEIAA in their meeting dated 14-02-22 closed this case with direction to PP as “PP should apply afresh as per procedure laid down in the MoEF&CC’s OM vide no. E 138949 dated 28.01.2022 & OM regarding SoP dated 07.07.2021. The SoP has come into force and the violation projects have to be considered accordingly.” Case closed vide letter no. 3150-51/SEIAA/22 dated 26-02-22.

PP has applied with fresh application which was forwarded online by SEIAA to SEAC for appraisal. The committee observed that in the 541st SEAC meeting dated 20.01.2022 it was recorded that -

The committee after detailed discussion it was observed that the as per factual status submitted by Office of the Chief Engineer Narmada Tapti Basin, WRD, Indore, vide letter No. vide no. 479/work/-26/NT/21, dated 23.11.2021 of Shri N.N. Gandhi, Chief Engineer, N-T Basin WRD, Indore. As per the submitted report By C.E. WRD, it is very much clear that they have carried out the partial construction work.

“Earth work has been carried out in 1693.50 lengths of left and right flanks of proposed dam. This work has been done non- overflow section. A sluice well has been constructed on RD 1605 m for discharge of River water. Construction work of spillway in nalla portion was restricted at original river bank level to maintain natural flow of water. Nalla closure has not been done. At present no work is being done in head works. The laying of pipelines for pressurized irrigation system in the command area is under process.

So, as per the submitted report by Office of the Chief Engineer Narmada Tapti Basin, WRD, Indore, vide letter No. vide no. 479/work/-26/NT/21, dated 23.11.2021 of Shri N.N. Gandhi, Chief Engineer, N-T Basin WRD, Indore, factual status is very much clear so committee feels there is no need of further site visit is required.

In this context PP should furnished implementation of Environmental Management Plan, comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan as mentioned in the MOEF&CC Notification New Delhi, the 8th March, 2018 S.O. 1030 (E) and submit present status of court direction through SEIAA.

Hence this case scheduled for praesentation wherein Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon along with

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

PP's as Project Incharge Ms. Megha Chourey, E.E., Division Khandwa and Ms. Divayani Billore E.E. , SCADA Office , Bhopal, from Water Resources Department, Govt. of M.P, and M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon, wherein PP submitted following points:-

- The proposed Aulliya medium irrigation project has been planned to meet the drinking and irrigation water requirement of 13 villages falling in Khalwa tehsil of Khandwa district.
- The project is designed to serve a culturable command area of 5000 ha through lift irrigation during rabi season.
- To meet the water storage requirement, the project envisaged construction of a 1782 m long and 20.80 m high dam across Ghorapachhar river near Roshni village. This will create gross storage capacity of 26.246 MCM and live storage of 22.199 MCM.
- The project is being implemented and operated by Water Resources Department, Madhya Pradesh.
- Being an irrigation project with 5000 ha CCA, the project is covered under EIA notification, 2006 and prior environment clearance is applicable (Category B2).
- Scoping clearance was accorded by SEIAA (Case No. 5584/2017) vide their letter number 544/PS-MS/MPPCB/SEAC/TOR(297)/2017 dated 13/12/2017.
- Hard copy of EMP report of the project was submitted vide letter dated 02.11.2018. EMP report was submitted online vide proposal no. SIA/MP/ RIV/ 167713/2020 dated 07.01.2021. Essential details for the project (EDS) was further sought by SEIAA on 17.03.2021. Finally hard copy of EMP report was again submitted to SEIAA office personally by the EE, WRD on 24.07.2021.
- Construction work at site started before obtaining prior environment clearance and therefore it is considered a case of violation as per EIA notification, 2006 including various amendments.
- Till January 2021, when the work was halted at site substantial work has been completed.
- Ministry of Environment Forests & Climate Change vide its OM dated 28/01/2022, has reinstated the Standard Operating Process (SOP) as per the order dated 09/12/2021 of Hon'ble Supreme Court of India.
- Aulliya Medium irrigation Project falls under permissible project under EIA notification (Para 11, Step 3, Para B of SOP), therefore, Terms of Reference is requested.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Status report of constriction and development work done so far.
2. Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
3. Project description, its importance and the benefits.
4. Under energy conservation plan detail-out solar light erection panels.
5. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
6. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
7. Land acquisition, R & R details; does issues of R&R appeared in H'ble High court has been resolved - status their of ?
8. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
9. Baseline environmental study for ambient air (PM₁₀, PN_{2.5}, SO₂, NO_x & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
10. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
11. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
12. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
13. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

14. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
15. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
16. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
17. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
18. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
19. Comprehensive Plantation scheme shall be discussed in EIA report.
20. Status of court case till date with all supporting document.
21. Dam breack analysis shall be carried out.
22. Details of tree cutting proposed with their details inventory in forest area.
23. Details of trees to be felled in revenue area and how this issue will be adreesed shall be discussed in the EIA report.

10. Case No 9062/2022 Kumari Mamta Babulal, Owner, Village - Asrawad Bujurg, Tehsil & Dist. Indore, MP - 452010 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.80 ha. (10000 cum per annum) (Khasra No. 199/1/2), Village - Malikhedi, Tehsil - Bicholi Hapsi, Dist. Indore (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 199/1/2), Village - Malikhedi, Tehsil - Bicholi Hapsi, Dist. Indore (MP) 1.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/03/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 542 दिनांक 24/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 2.80 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एकल प्रमाण-पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 542 दिनांक 24/02/2022 के अनुसार प्रस्तावित खदान से 4.96 किलोमीटर दूर रालामण्डल अभ्यारण्य है अतः एन.बी.डब्ल्यू.एल. (National Board for Wildlife) से अनुमति हेतु आवेदन क्रमांक **FP/MP/QR/6232/20222**, दिनांक 19/2/22 को किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 165 मीटर पर, पश्चिम दिशा में 215 मीटर पर शेड है, पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर कच्चा रोड़ है तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 250 मीटर पर रेणुका माता का मंदिर भी स्थित हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्ष 2014 तक खनन कार्य किया गया है एवं उसके उपरांत खदान बंद है। समिति ने पाया कि परियोजना के प्रस्तावित स्थल का गूगल इमेज (11/2017 तथा 04/2021) के अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है तथा लीज में एक पेड 10/2020 की गूगल इमेज में दिख रहा है जो वर्तमान में काटा जा चुका है, इस प्रकार यह प्रकरण ई.आई.आई नोटिफिकेशन, 2006 के अनुसार वॉयलेशन (Violation) का प्रकरण है। अतः इस स्थिति में इस प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता तथा एकल प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रस्तावित खदान से रालामण्डल अभ्यारण्य 4.96 किलोमीटर दूर होने के कारण (05 किलोमीटर से कम) प्रकरण श्रेणी-ए का है अतः नस्ती सिया को आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जावे।

11. Case No 9063/2022 M/s Baghel Construction, Prop. Shri Pushpraj Singh Baghel, House No. 476, Ward No.9 Gandhigram, Tehsil - Sihora, Dist. Jabalpur, MP - 483222, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 3.55 ha. (20854 cum per annum) (Khasra No. 574, 575 (Part)), Village - Devnagar, Tehsil - Sihora, Dist. Jabalpur (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 574, 575 (Part)), Village - Devnagar, Tehsil - Sihora, Dist. Jabalpur (MP) 3.55 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/03/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 667 दिनांक 02/03/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 185 मीटर पर रोड, उत्तर-पश्चिम दिशा में 265 मीटर पर नहर, उत्तर दिशा में 170 मीटर पर आबादी तथा 185 मीटर पर शेड स्थित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आंशिक क्षेत्र के दक्षिण दिशा में खदान से सटा हुआ एक पॉली हाऊस बना हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है एवं खदान में काम चालू नहीं है इसलिए किसान ने उनके क्षेत्र के अंदर तक यह बना लिया है तथा जैसे ही कार्य चालू होगा उसके द्वारा इसे हटा लिया जायेगा । प्रस्तुतीकरण कारण के दौरान पी.पी. ने बताया कि उत्खनन के दौरान कोई भी वृक्ष नहीं काटा जायेगा तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो पिट दिख रहा है वह पुराना है, जिसका माइन प्लॉन में उल्लेख है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ लीज क्षेत्र में पिट दिख रहा है, उसका उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/3/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मरुम - 20854 मी.3 प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.23 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु.07.63 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख :-

आगमी 01 वर्ष तक	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
	ग्राम देवनगर में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र की मरम्मत का कार्य कराया जायेगा तथा इसी आंगनवाड़ी केंद्र में 2 टेबल, 4 कुर्सियां, 2 पंखे, खेल सामग्री एवं स्टेशनरी उपलब्ध करवाई जाएगी ।	30,000/-
योग		30,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4260 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
-----	------------	---------------------	--------

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान		(संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, सफ़ेद केस्टर, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000 पौधे
2	परिवहन मार्ग में	करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	350 पौधे
3	ग्राम के विद्यालय परिसर में उपलब्ध क्षेत्र पर	चिरोल, नीम, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कचनार, कदम्ब करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200 पौधे
4	ग्राम के मुक्तिधाम परिसर में उपलब्ध क्षेत्र पर	पुत्रंजीवा, पीपल, कचनार, कदम्ब करंज, मोलश्री, चिरोल, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	350 पौधे
5	ग्राम देवनगर में ग्रामवासियों एवं पंचायत से परामर्श लेकर	करंज, आवला, जंगल जलेबी, हर्षा, चिरोल, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2360 पौधे
		कुल वृक्षारोपण	4260 पौधे

- 12. Case No 7544/2020 M/s Satguru Cements Private Limited, 601/1, Airen Heights, Scheme No. 54, PU - 3, Oppo. C - 21 Mall, AB Road, Indore, MP Prior Environment Clearance for Limestone Deposit in an area of 58.431 ha. (3,32,448 tonne per annum) (Khasra No. 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 126, 137/2, 133, 141/1, 144, 146/2 (Part)), Village - Khod, Tehsil - Gandhwani, Dist. Dhar (MP) Environmental Consultant:M/s Creative Enviro Services, Bhopal.**

This is case of Limestone Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 126, 137/2, 133, 141/1, 144, 146/2 (Part)), Village - Khod, Tehsil - Gandhwani, Dist. Dhar (MP) 58.431 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 455वीं दिनांक 16/09/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

प्रकरण आज दिनांक 12/03/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । समिति द्वारा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण एक और अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का समिति निर्णय लेती है फिर भी यदि परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो यह प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा ।

13. Case No 8663/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorized Signatory, Village - Manpur, Tehsil & Dist. Anuppur, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.360 ha. (96480 cum per annum) (Khasra No. 75/78, 37/77), Village - Manpur, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP). Env. Consultant M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida, UP.

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 75/78, 37/77), Village - Manpur, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 5.360 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 518वीं दिनांक 08/10/2021 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

आज दिनांक 12/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक / पर्यावरण सलाहकार द्वारा रेत खदान के बारे में निम्न प्रमुख जानकारी दी गई :-

यह रेत खदान सोन नदी पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है । बैठक के दौरान समिति अनुमोदित खनन योजना के चेप्टर-04 "रिप्लेनिशमेंट स्टडी" के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन कार्यालय (खनिज शाखा) जिला उमरिया, म.प्र., द्वारा किया गया है। समिति ने अपलोड की गई डी.एस.आर. जो खनिज अधिकारी, अनूपपुर ने पत्र क्रमांक 1396 दिनांक 13/7/21 (सत्र 2020-21) के माध्यम से जारी की है में इस खदान के विवरण पेज क्रमांक 19 सरल क्रमांक 06 पर उल्लेखित है । समिति ने ऑनलाईन संलग्न डी.एस.आर. का अवलोकन किया तथा यह पाया कि डी. एस. आर. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुरूप नहीं है। अतः समिति द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/7/18 के अनुरूप एप्राजल नहीं किया जा सका ।

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य (स्कूल की मरम्मत, स्वास्थ्य शिविर) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय अपनाये जायेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ब अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 96,480 मी.³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.47 लाख एवं रिकरिंग 04.39 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु.01.60 लाख :—

क्रं.	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रु. में
01	ग्राम मानपुर के प्राथमिक विद्यालय में दीवार की मरम्मत व शौचालय का दरवाजा लगवाया जाएगा।	1,00,000
02	स्थानीय ग्रामीणों के लिए बीपी व शुगर पेशेंट के लिए मेडिकल कैंप वर्ष में 02 बार लगवाएंगें।	60,000
सड़क का निर्माण		ईएमपी में पहले से ही शामिल है।
ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण		
पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद ग्राम मानपुर के 36 लोगों को रोजगार दिया जाएगा।		
(आगामी एक वर्ष तक) योग		

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6432 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के तट पर।	कटंग बॉस, नागरमोथा, खस स्लिप एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	850
2	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ व	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, चिरोल, खमैर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
3	ग्राम मानपुर के ग्रामवासियों व किसानों में वितरण हेतु	इमली, आंवला, कटहल, आम, मुनगा, अमरुद, जामुन अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	4562
4	विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	20
योग			6432

14. Case No 8258/2021 The Executive Engineer, Narmada Development Division No. 19, Bhikangaon, Dist. Khargone Prior Environment Clearance Khalwa Lift Micro Irrigation Project at 59 Vilages of Tehsil - Khalwa, Dist. Khandwa (MP). Env. Cons.: Dr. Ram Prasad from M/s. Forest Environment & Climate Management (FECCM) Private Limited, Bhopal MP.

This is case of Prior Environment Clearance Khalwa Lift Micro Irrigation Project at 59 Vilages of Tehsil - Khalwa, Dist. Khandwa (MP).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 487th SEAC dated 05/03/2021 wherein ToR was recommended.

Background of the Project

- Khalwa Lift Micro Irrigation Scheme, EE NVDA Division 19: comprising of lifting of 11.25 cumecs water for irrigation in CCA of 35103 hectares and GCA of 47905 hectares from Submergence of ISP reservoir for providing water for Micro-irrigation up to 2.5-hectare chak with residual head of 23 meters at 2.5-hectare chak.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

- Lifting Point: ISP Reservoir Near Village Baidiyaw/Nandgaon
- The project has been conceived to cater irrigation water to about 59 villages in Khalwa Tehsil, District Khandwa (East Nimar).
- Power consumption (including all types of power) in the whole system should not exceed 31.04 MW at the time of commissioning and 32 MW in 15 years lifetime.

PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by Mr. Parikshit Agrawal Env. Consultant from M/s. Forest Environment & Climate Management (FECCM) Private Limited, Bhopal along with PP's Shri R.S. Gupta, E.E. (Khalwa Project), Narmada Development Division No. 19, Bhikangaon, Dist. Khargone, MP, with the following details of the project:

During presentation, PP submitted that project involves approx 4.8 ha., forest area for F.C., they have applied vide online application no. FP/MP/IRRIG/125648/2021 dated 07/10/2021 and is under consideration. The committee recommended that as per MoEF&CC OM no. 5/11013/41/2006-II-A (I) this case may be forwarded to SEIAA and PP shall submit document of forest clearance to SEIAA. PP further submitted following points about the project:

- Khalwa Lift Micro Irrigation Scheme, EE NVDA Division 19: comprising of lifting of 11.25 cumecs water for irrigation in CCA of 35103 hectares and GCA of 47905 hectares from Submergence of ISP reservoir for providing water for Micro-irrigation up to 2.5-hectare chak with residual head of 23 meters at 2.5-hectare chak.
- Lifting Point: ISP Reservoir Near Village Nandgaon tehsil Harsud District Khanda.
- Power consumption (including all types of power) in the whole system should not exceed 31.04 MW at the time of commissioning and 32 MW in 15 years lifetime.
- Project Benefits - The project will bring water to 59 villages of Khalwa Tehsil, District Khandwa(East Nimar)., which are presently water scarce and cannot irrigate their land efficiently due to shortage of water. The project will bring direct environment and social benefits, which in turn will bring

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

prosperity to the area and increase spending power of farmers, bringing economic benefits to the region.

- No protected area within 10 km. Nearest PA (Project boundary is 120 km from Ralamandal wildlife sanctuary and 31 km from proposed Omkareshwar wildlife sanctuary .) .
- The pipe shall be laid minimum 1.00 m. below average ground level. Hence no land for pipes shall be acquired permanently, except for Pumphouses . Temporary Land acquisition for pipe line laying will be done as per duct act.
- The rising main shall be aligned in such a way, that it traverses minimum in forest area and the total length from lifting to delivery point becomes shortest.
- For construction of pump houses, and distribution chamber of the Scheme, private land of about 3.2 Ha has been acquired.
- Command Area - The command area is the area of Khalwa micro lift irrigation scheme covering 35,103 ha land which will be irrigated by drip/sprinkler irrigation under the proposed micro lift irrigation scheme. Entire command falls within the study area.
- It is proposed to construct the scheme in 42 months and the command will also be developed in 3 stages as detailed below:

Particulars	2021-22	2022-23	2023-24
1. Construction of pump house & rising main	10%	60%	30%
2. Construction of piped distributaries	5%	60%	35%
3. Construction of Disnet	00	50%	50%
4. Development of irrigation (in ha.)	00	10000	25103

After presentation committee asked PP to submit response on following information :

1. Current status of Forest Clearance Stage –I .
2. PP commitment that no R&R is involved.
3. Detailed muck management plan considering top soil & bottem soil management.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

4. PP's commitment and proposal regarding plantation scheme as suggested by the committee.
5. Under CER include training for effective water utilization activity and proposal for distribution of supplementary nutrition foods in the village anganwadi's coming under command area Development (CAD) with physical targets.

PP submitted the reply vide letter dated 12.03.2022 which were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Khalwa Lift Micro Irrigation Project at 59 Vilages of Tehsil - Khalwa, Dist. Khandwa (MP), GCA- 47,905 ha., CCA CCA of 35,103 ha. Cat. 1(c) River Valley Project Valley and Hydroelectric Projects subject to the following special conditions and obtaining FC clearance for diversion of 4.80 ha. forest land:

I. Statutory compliance:

- i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.
- ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife. (If applicable)
- iii. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (in case of the presence of any schedule-I species in the study area). (If applicable)
- iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee. (If applicable)
- v. NOC shall be obtained from National Commission of Seismic Design Parameters (NCSDS) of CWC. (If applicable)
- vi. Necessary approval of CEA shall be obtained for those projects having the project cost more than Rs. 1,000 crores. (If applicable)

II. Air quality monitoring and preservation

- i. Regular monitoring of various environmental parameters viz., Water Quality,

Ambient Air Quality and Noise levels as per the CPCB guidelines at designated locations shall be carried out on monthly basis and a detailed database of the same shall be prepared and recorded. This shall be used as a baseline data for post construction EIA / Monitoring purposes.

- ii. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed standards.
- iii. Necessary control measures such as water sprinkling arrangements, etc. are to be taken up to arrest fugitive dust at all the construction sites.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. Mixed irrigation shall be practiced and necessary awareness be given to all the farmers and trained in the use of such systems. Proper crops selection shall be carried out for making irrigation facility more effective.
- ii. On Farm Development (OFD) works like landscaping, land leveling, drainage facilities, field irrigation channels and farm roads, etc. should be taken up in phased manner prior to the start of irrigation in the entire command area. The Command Area Development Plan should be strictly implemented as proposed in the EIA/EMP report.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures be provided so as to meet the ambient noise standards as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, as amended in 2010 under the Environment Protection Act (EPA), 1986.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time .

V. Waste Management

- i. Approximately 1,71,775 m³ of muck will be generated along the pipeline length.
- ii. Almost 400 m³ of muck will be needed to manage on daily basis, fourtrucks and Five Trolleys along side by side with the excavation will be sufficient to manage the muck in multiple no. of trips.
- iii. Muck disposal be carried out only in the approved and earmarked sites. The dumping sites shall be located sufficiently away from the HFL of the river. Efforts be made to reuse the muck for construction and other filling purposes and balanced be disposed of at the designated disposal sites. Once the muck

disposal sites are inactive, proper treatment measures like both engineering and biological measures be carried out so that sites are stabilized quickly.

- iv. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

VI. Green Belt & Plantation

- i. Total of 2.0 ha. of green belt shall be developed, detailed plantation scheme will be prepared by implementing agency/ forest department and approved by competent authority. A provision of 100 Lakhs has been made under compensatory afforestation.
- ii. Plantation: - identification of areas/patches along with species will be done with the instruction of DFO Khandwa/Forest wing of NVDA.
- iii. Any plantation within the forest area shall be carried –out with the consent of local DFO.
- iv. During excavation care will be taken that top fertile soil is kept aside and will not be used for filling the excavated area after laying pipe line. This top soil will be spread on adjoining farming fields with consent of farmers or alternatively will be used for green belt development.
- v. To enrich the habitat of the project site, plantation shall be raised as envisaged in the EIA/EMP report. Plantation to be developed along the periphery of the reservoir in multi-layers with local indigenous species in consultation with the local State Forest Department.
- vi. Compensatory forestation programme shall be implemented as per the approved plan which shall be monitored by M.P. Bio Diversity Board, Bhopal.

I. EMP & CER

- i. A budgetary provision of Rs. 633.105 Lakha is made for Environmental Management Plan as capital and Rs. 715.067 Lakhs as recurring cost. Out of which
 - a provision of 100.0 Lakhs has been made under compensatory Afforestation, and
 - Training to benefited farmers of command area for effective utilization of water will be provided for which provision of 64.46 Lakhs has been made under public awareness program.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

- ii. Under CER following physical target based activities based on public hearing has proposed by PP :
 - Supplementary nutrition food will be supplied to all Anganwadi covered in the command area for which provision of 10.0 Lakhs will be made under public health delivery system.
 - Awareness for local hygiene and social activities in registered Gaushala (Devi Ahliya Mata Gaushala, Village – Pedmi, Dist.- Indore) (Rs. 2.5 lakhs).
- iii. Formation of Water User Association/Co-operative be made by involvement of the whole community be ensured for discipline use of available water for irrigation purposes.

VII. Miscellaneous

- i. Considering the shifting of huge volume of muck, which will be generated during the construction phase, project proponent shall construct pucca transportation road(s), from muck generation site(s) to the dumping site(s).
- ii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- iii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- iv. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company
- v. The project proponent shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- vi. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.
- vii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- viii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

(MoEF&CC).

- ix. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- x. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

15. Case No 9064/2021 Shri Sanjay Tiwari, 1074, Shukla Nagar, Indira Gandhi Ward, Garha, Ghana, Dist. Jabalpur, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.31 ha. (50,003 cum per annum) (Khasra No.92, 95), Village - Ghaghra, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No.92, 95), Village - Ghaghra, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) 3.31 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 694 दिनांक 02/03/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 17.35 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 429 मीटर पर आबादी, उत्तर-पश्चिम दिशा में 520 मीटर पर पक्का रोड़ है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टैण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 मार्च 2022

1. खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 429 मीटर पर आबादी है, अतः इनके संरक्षण की योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में प्राकृतिक नाला है, जिसके लिए प्रोटेक्शन प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें ।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।

CORRIGENDUM

16. Case No 8948/2022 Shri Ruplal Kol S/o Shri Premlal Kol, Village - Temar, Tehsil & Dist. Jabalpur, MP - 482051, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.60 ha. (12000 cum per annum) (Khasra No. 142/5), Village - Amjhar, Tehsil - Kundam, Dist. Jabalpur (MP).

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 10/03/2022 द्वारा सूचित किया है कि उनका प्रकरण एसईएसी की 558वीं बैठक दिनांक 04/03/2022 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित एसईआईए को प्रेषित किया गया है, जिसमें 500 मीटर 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, होने एवं खदान के दक्षिण दिशा में 90 मीटर पर एक नहर स्थित होने का उल्लेख करते हुए एम.एम.आर., 1996 के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र (100 मीटर) की सीमा के अंदर है अतः 10 मीटर का सेड-बैंक छोड़े जाने का उल्लेख हो गया है, त्रुटिवश टंकण हो गया है, खदान के उत्तर-पूर्वी दिशा में 160 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट है, जिस हेतु 40 मीटर का सेट-बैंक है परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान दिया जा चुका है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त हेतु शुद्धि पत्र जारी करने का अनुरोध किया है । समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा यह पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश गलत टंकित हो गया है । अतः समिति अपनी 558वीं बैठक दिनांक 04/03/2022 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कि 500 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित के स्थान पर कोई अन्य खदान नहीं है एवं खदान के दक्षिण दिशा में 90 मीटर पर एक नहर स्थित है जो एम.एम.आर., 1996 के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र (100 मीटर) की सीमा के अंदर है अतः 10 मीटर का सेड-बैंक छोड़े जाने के स्थान पर खदान के उत्तर-पूर्वी दिशा में 160 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट है, जिस हेतु 40 मीटर का सेट-बैंक पढ़े जाने की अनुशंसा करती है, शेष शर्तें/अनुशंसा यथावत रहेंगी ।

17. Case No 8099/2021 M/s Italian Marble, Gautam Mohalla, Jalpa Devi Ward, Dist. Katni, MP - 483501 Prior Environment Clearance for Marble and salable Waste Mine in an area of 8.21 ha. (57,390 cum per annum) (Khasra No. 406, 417), Village - Pondi, Tehsil - Dhimarkhera, Dist. Katni, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 09/03/2022 द्वारा सूचित किया है कि उनका प्रकरण एसईएसी की 548वीं बैठक दिनांक 10/02/2022 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित एसईआईए को प्रेषित किया गया है, जिसमें मार्बल एवं सेलएबल रिजेक्ट-14029 घनमीटर/वर्ष त्रुटिवश टंकण हो गया है, जबकि समिति की 489वीं बैठक दिनांक 12/03/21 को जारी पुनरीक्षित टॉर एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों में मार्बल एवं सेलएबल रिजेक्ट-57,390 घनमीटर/वर्ष है। अतः परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त हेतु शुद्धि पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा यह पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश गलत टंकित हो गया है। अतः समिति अपनी 548वीं बैठक दिनांक 10/02/2022 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित मार्बल एवं सेलएबल रिजेक्ट-14029 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर मार्बल एवं सेलएबल रिजेक्ट-57,390 घनमीटर/वर्ष पढ़े जाने की अनुशंसा करती है, शेष शर्तें/अनुशंसा यथावत रहेंगी।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

- b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

560वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च 2022

- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

- नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.